



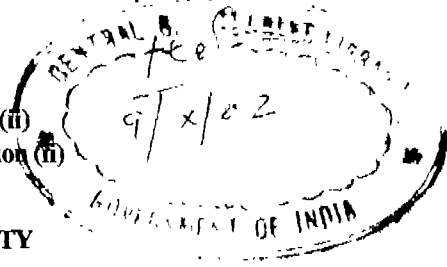
# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 471 ]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2002/वैशाख 31, 1924

No. 471]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2002/VAISAKHA 31, 1924

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 21 मई, 2002

का.आ. 551(अ).—**यतः** माननीय वित्त मंत्री ने 13 मार्च 2001 को संसद में घोषणा की थी, कि "स्टाक एक्सचेंजों का निगमीकरण जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, और व्यापारिक सदस्यता को एक दूसरे से अलग रखा जायेगा। प्रशासनिक कदम उठाये जायेंगे और तदनुसार, विधायी परिवर्तन, यदि अपेक्षित हो, प्रस्तावित किये जायेंगे।" उपर्युक्त, नीति घोषणा के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) ने समय समय पर स्टॉक एक्सचेंजों के साथ अपरस्पर्ीकरण के मुद्दे पर चर्चा की थी और

**यतः** भाप्रविबो बोर्ड ने 28 दिसंबर 2001 को आयोजित इसकी बैठक में स्टॉक एक्सचेंजों के अपरस्पर्ीकरण के मुद्दे पर चर्चा की और विनिश्चय किया कि अब से कोई सदस्य बलाल एक्सचेंज का पदाधिकारी नहीं होगा जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि का पद धारण करना है, और एक्सचेंजों के निगमीकरण और अपरस्पर्ीकरण के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के अन्य प्रशासनिक और विधिक तौरतरीके निर्धारित किये जा रहे हैं; और

**यतः** तत्पश्चात् भाप्रविबो ने परिपत्र सं. एसएमडी/पॉलिसी/सीआइआर-2/2002 तारीख 10 जनवरी, 2002 द्वारा, द कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज असोसिएशन लि (इसमें इसके पश्चात् "कस्टाए" के रूप में निर्दिष्ट) को सम्मिलित करते हुए सभी एक्सचेंजों को कथित आदेश की तारीख से दो मास के भीतर, उनके नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि को उपयुक्त रूप से संशोधित करते हुए भाप्रविबो बोर्ड विनिश्चय कार्यान्वित करने का निदेश दिया; और

यतः भाप्रविबो ने पत्र सं. एसएमडी /सीएसई/एडीएमएन/4536/02 तारीख 19 मार्च 2002 द्वारा कस्टाए को पुष्टि करने की सलाह दी कि क्या उन्होंने भाप्रविबो परिपत्र सं. 2 द्वारा जारी 10 जनवरी 2002 के भाप्रविबो निदेश का अनुपालन किया था, जिसके द्वारा निदेश की तारीख से दो मास की कालावधि के भीतर कोई भी सदस्य दलाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने के लिए अनुज्ञात नहीं था और कस्टाए को यह पुष्टि करने की भी सलाह दी गयी कि उन्होंने भाप्रविबो बोर्ड द्वारा लिये गये उपर्युक्त विनिश्चय को और इस संबंध में सरकार के नीति विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए नियम, संगम अनुच्छेद इत्यादि को उपयुक्त रूप से संशोधित किया था या नहीं; और

यतः ऊपर उल्लिखित पत्र और परिपत्र तारीख 10 जनवरी 2002 के उत्तर में, कस्टाए ने इसके पत्र तारीख 19.3. 2002 द्वारा सूचित किया कि आचरण के आदर्श नियम के कार्यान्वयन के पश्चात् कथित निदेश सम्मिलित किया जायेगा और कि एक्सचेंज के संगम स्थापन और अनुच्छेद में समिति /भाप्रविबो/ शेयरधारकों के साधारण निकाय द्वारा इसके अनुमोदन के पश्चात् समुचित परिवर्तन किये जायेंगे, कि प्रक्रिया आरंभ हो गयी है और

यतः अधिकांश स्टॉक एक्सचेंजों ने 10.1.2002 के आदेश को प्रभावी करने के लिए उनके नियमों / संगम अनुच्छेदों में संशोधन किया है, और कस्टाए उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए संगम अनुच्छेद का संशोधन करने में असफल रहा है, भाप्रविबो की राय है कि विनिधानकर्ताओं और पूँजी बाजार के हित में, लोक हित में भी, संगम अनुच्छेद को संशोधित करना आवश्यक और समीचीन है, इस आदेश में उपदर्शित रीति में, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित कारणों के लिए, अर्थात् :

- (i) स्टॉक एक्सचेंजों के शीघ्र निगमीकरण के लिए जिसके द्वारा स्वामित्व, प्रबंधन, और व्यापारिक सदस्यता को स्टॉक बाजारों में संस्थागत प्रणालीतंत्र और व्यापार पद्धतियों को उन्नत करने के लिए एक दूसरे से अलग रखा जायेगा।
- (ii) इसके अलावा, बोर्ड देश के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों के शासी बोर्ड की संरचना के संबंध में नियम, विनियम और उप-विधियों में एकरूपता बनाये रखने के लिए इसे वांछनीय पाता है।

अतः अब भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कथित अधिनियम की धारा 29क के अधीन जारी इसकी अधिसूचना सं. का.आ. /573(अ) तारीख 3 जुलाई 1992 के अधीन भाप्रविबो द्वारा बोर्ड को प्रत्यायोजित शक्तियों के साथ पठित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कस्टाए के संगम अनुच्छेद में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :

1. अनुच्छेद 82ड. खंड (i) में, शब्द "समिति के" बाद और शब्द "सदस्य" के पहले दिया हुआ शब्द "निर्वाचित" हटा दिया जायेगा।

2. अनुच्छेद 82 ड. के खंड (i) में, विद्यमान परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जायेगा:

"परंतु यह और कि एक्सचेंज का कोई दलाल सदस्य एक्सचेंज का पदाधिकारी अर्थात् अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष नहीं होगा।"

[ फा. सं. भाप्रविबो/विधि/8716/02 ]

जी. एन. बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st May, 2002

S.O. 551(E).—**Whereas** the Hon'ble Finance Minister had announced in the Parliament on March 13, 2001, that "corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other. Administrative steps will be taken and legislative changes, if required, will be proposed accordingly." In accordance with the above, policy announcement, The Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI") had discussed the issue of demutualisation with the stock exchanges from time to time and

**Whereas** SEBI Board in its meeting held on December 28, 2001, discussed the issue of demutualisation of the stock exchanges and decided that henceforth no broker member shall be an office bearer of an exchange that is hold the position of the President, Vice-President, Treasurer etc., and the other administrative and legal modalities for corporatisation and demutualisation of exchanges of the stock exchanges are being worked out; and

**Whereas** subsequently, SEBI directed all the exchanges including The Calcutta Stock Exchange Association Ltd. (hereinafter referred to as "CSE") vide circular no. SMD/POLICY/CIR-2/2002 dated January 10, 2002, to implement the SEBI Board decision by suitably amending their Rules, Articles of Association etc., within two months from the date of the said Order; and

**Whereas** SEBI advised C7SE vide letter no. SMD/CSE/ADMN/4536/02 dated March 19, 2002 to confirm whether they had complied with the SEBI directive of January 10, 2002, issued vide SEBI Circular no. 2, whereby no broker member was allowed to hold office as President, Vice-President within a period of two months from the date of the directive and CSE was also advised to confirm whether they had suitably amended the Rules, Articles of Association etc., to give effect to the above decision taken by the SEBI Board and the policy decision of government in this regard; and

**Whereas** in response to the above mentioned letter and circular dated January 10, 2002, CSE vide its letter dated 19.3.2002 informed that the said directive shall be incorporated after implementation of model rules of conduct and that appropriate changes will be made in the memorandum and articles of association of the exchange after its approval by the committee/SEBI/general body of shareholders, that the process has been initiated and

**Whereas** most of the stock exchanges have amended their rules/articles of association to give effect to the order of 10.1.2002, and there is failure on the part of CSE to amend the articles of association in the light of the above, SEBI is of the opinion that in the interests of the investors and the capital markets, as also in public interest, it is necessary and expedient to amend the Articles of Association, in the manner indicated in this Order, inter-alia for the following reasons namely:

- (i) To expedite the corporatisation of stock exchanges by which ownership, management, and trading membership would be segregated from each other to improve institutional mechanism and trading practices in the stock markets.
- (ii) Moreover, the Board finds it desirable to maintain uniformity in the Rules, Regulations and Bye-laws regarding composition of the Governing Board of various stock exchanges in the country.

**Now**, therefore in exercise of the powers conferred by Sub-section 2 of Section 8 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 read with the powers delegated to the Board by the SEBI under its notification no. S.O / 573(E) dated July 3, 1992 issued under Section 29A of the said Act, Securities and Exchange Board of India makes the following amendments to the Articles of Association of CSE namely:-

1. In clause (i) Article 82E, the word "elected" appearing after the words "amongst the" and before the word "member" shall be deleted
2. In clause (i) of Article 82 E, after the existing proviso, the following proviso shall be added:

" Provided further that no broker member of the exchange shall be an office bearer i.e. President, Vice President or Treasurer of the exchange."

[F.No. SEBI/LE/8716/02]

G. N. BAJPAI, Chairman

1639-21/02-2

